

संपादकीय

बच्चों को गहरा नुकसान

कोर्ट ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस ने एडिविक्ट डिजाइन फीचर्स बनाए। बच्चों पर उनके संभावित दुष्प्रभाव के बारे में उन्होंने पूर्व चेतावनी नहीं दी। इस कारण कोर्ट ने उन पर लगभग 60 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने प्लैटफॉर्म पर जानबूझ कर ऐसी तकनीकी व्यवस्था की है, जिससे यूजर्स को उन पर बने रहने की लत लग जाती है। खासकर बच्चों को इससे गहरा नुकसान हो रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक दूरगामी महत्त्व का फैसला दिया। उसमें सोशल मीडिया कंपनियों मेंटा (इंस्टाग्राम) और गूगल (यूट्यूब) को बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य हानि पहुंचाने का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने पाया कि इन प्लेटफॉर्मस ने एडिविक्ट डिजाइन (लत डालने वाले) फीचर्स बनाए। बच्चों पर उनके हो सकने वाले दुष्प्रभाव के बारे में उन्होंने कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी। इस कारण कोर्ट ने उन कंपनियों पर लगभग 60 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह फैसला एक 20 वर्षीय महिला की याचिका पर आया, जिसने बताया कि बचपन से ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब के उपयोग ने उसके जीवन पर खराब असर डाला और उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाईं। इस फैसले को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए पहला बड़ा कानूनी झटका माना गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब मेंटा और गूगल जैसी कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म डिजाइन बदलने और उन्हें बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए दबाव बढ़ेगा। मगर ये बात अमेरिका के अंदर की है। बाहर में जब कभी किसी देश ने इन कंपनियों पर लगात लगाते की कोशिश की है, अमेरिका सरकार अपनी कंपनियों के बचाव में आ खड़ी हुई है। डॉनल्ड ट्रंप के शासनकाल में यह प्रवृत्ति अधिक आक्रामक नजर आई है। विनियमन की यूरोपियन यूनियन की कोशिश के खिलाफ ट्रंप खुद मोर्चा संभाले रहे हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की पहुंच रोकने के ठोस कदम उठाए हैं। भारत में भी ऐसी चर्चा हाल में तेज हुई है। कर्नाटक सरकार ने इस दिशा में पहल की है। मगर जब ऐसा कदम केंद्र के स्तर पर नहीं उठाया जाता, उसके प्रभावी होने की संभावना नहीं है। अतक नरेंद्र मोदी सरकार को कम-से-कम इस मामले में अमेरिकी दबाव की परवाह ना करते हुए ठोस वैधानिक पहल करनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ कंज्यूमर समझने वाली कंपनियों को विनियमित करने की अति-आवश्यकता है।

भारत की जनगणना 2027 बदलते भारत की नई कहानी

रमेश जायभाये,

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की छोटी-सी जानकारीकृजैसे पानी, बिजली या परिवार के सदस्यों का विवरणकृदेश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकती है? दरअसल, हर नागरिक की दी गई जानकारी मिलकर ही भारत के भविष्य की दिशा तय करती है। इसी कड़ी में वर्ष 2027 की जनगणना एक खास पड़ाव बनने जा रही है। यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि बदलते भारत की एक नई कहानी हैकृएक ऐसी कहानी जिसमें हर नागरिक की भागीदारी है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल अंदाज में होगी, जो इसे पहले की सभी जनगणनाओं से अलग और अधिक आधुनिक बनाती है। छत्तीसगढ़ में इस महाअभियान को लेकर तैयारियाँ तेजी से पूरी की जा रही हैं। वातावरण ऐसा है मानो कोई बड़ा जनउत्सव आने वाला होकृऔर वास्तव में, यह एक ऐसा अभियान है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। कहानी शुरू होती है इतिहास सेच भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और 1881 से इसे पूरे देश में व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना आयोजित हुई, जिसने देश के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। अब वर्ष 2027 की जनगणना इस ऐतिहासिक यात्रा का आधुनिक रूप है। यह न केवल देश की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी, बल्कि भविष्य की योजनाओं की नींव भी तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगीकृपहला चरण अप्रैल-मई 2026 में और दूसरा फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित किया जाएगा। राज्य के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 (रात 12 बजे) निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। अब आपकी बारीरू खुद करें अपनी जनगणना! इस बार जनगणना की सबसे रोचक और उपयोगी सुविधा हैकृस्व-गणना । अब आप स्वयं अपने घर और परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आपसे परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, शिक्षा, व्यवसाय और घर की सुविधाओं से जुड़े कुछ सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी जानकारी भरने के बाद आपको एक एसई आईडी प्राप्त होगी। जब प्रगणक आपके घर आएंगे, तो केवल यह पहचान दिखानी होगी और आपकी जानकारी सत्यापित कर ली जाएगीकृयानी बार-बार जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। आप जो जानकारी देंगे, वही दर्ज की जाएगी। स्व-गणना के प्रति लोगों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा हैकृदेशभर में लाखों परिवार इस सुविधा का उपयोग कर चुके हैं, जो इस डिजिटल पहल की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। स्मार्ट तकनीक, सटीक आंकड़े और भरोसेमंद प्रक्रिया इस बार जनगणना पूरी तरह तकनीक के सहारे संचालित होगी। प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा दर्ज करेंगे, जिससे काम तेज और अधिक सटीक होगा। साथ ही, आधुनिक जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग का उपयोग कर हर क्षेत्र और गणना ब्लॉक को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा रहा है, ताकि कोई भी घर या व्यक्ति छूट न जाए। डेटा के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए उन्नत डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहती है। एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, इस बार जाति संबंधी आंकड़ों का भी समावेश किया जाएगा, जो दशकों बाद समाज की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करेगा। जनगणना में समाज के हर वर्ग को शामिल करने का विशेष उपाय रखा जाता है। इसी के तहत बेचर व्यक्तियों की गणना भी अलग से, विशेष अभियान के माध्यम से की जाती है, ताकि कोई भी नागरिक इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। और जहाँ तक आपकी जानकारी की सुरक्षा का सवाल हैकृयह पूरी तरह गोपनीय रहती है। इसे किसी अन्य विभाग या एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाता। छत्तीसगढ़ तैयार, अब आपकी भागीदारी जरूरी छत्तीसगढ़ में इस अभियान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं। शहरों से लेकर गाँवों तक, हर क्षेत्र में जनगणना टीम सक्रिय रहेगी, ताकि कोई भी परिवार छूट न जाए।

विचार

बिहार में संभावनाएं विकास की अब सत्ता सम्राट की

ललित बिहार की राजनीति लंबे समय से बदलाव, प्रयोग और नेतृत्व के उतार-चढ़ाव का साक्षी रही है। ऐसे परिदृश्य में जब लंबे इंतजार और जटिल कूटनीतिक समीकरणों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन स्थापित होने की स्थिति बनती है और सम्राट चौधरी जैसे नेता मुख्यमंत्री के रूप में उभरते को हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत भी है। यह क्षण बिहार के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां अपेक्षाएं केवल शासन परिवर्तन की नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता, दृष्टि और परिणामों की भी हैं। नये मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के सामने न सिर्फ बिहार की जनता में एक कुशल प्रशासक की छाप छोड़ने की चुनौती है, बल्कि पार्टी की अपेक्षाओं एवं नीतीश कुमार द्वारा खींची रेखाओं से आगे निकलने के संघर्ष में भी उन्हें खरा उतरना होगा। सम्राट को उससे आगे ऐसा कुछ करना होगा, ताकि भाजपा उसके आधार पर भविष्य की दावेदारी पेश कर सके एवं अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की पात्रता विकसित कर सके। बिहार में भाजपा

लेकिन शहरी



उमेश बीते तीस मार्च को गृहमंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहे माओवादी और नक्सली आतंकवाद के खाल्ते का औपचारिक अंत की घोषणा कर दी है। चाहे माओवाद हो या नक्सलवाद, दोनों ही धाराएं उग्रपंथी वामपंथ से प्रभावित रही हैं। इनका मानना रहा है कि सत्ता बंदूक की नली या बारूद से निकलती है। इसी विचारधारा के तहत इस वैचारिकी ने भारत के तकरीबन एक तिहाई जिलों पर अरसे तक कब्जा आम रखा। इस विचारधारा से प्रभावित लाल आतंक एक दौर में पशुपति से लेकर तिरुपति तक फैला हुआ था। लेकिन अब यह निस्तेज हो चुका है। ज्यादातर नक्सली या माओवादी लड़के या तो हथियार डाल कर मुख्यधारा की जिंदगी में वापस लौट गए हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं। लेकिन अब भी इस विचारधारा से प्रभावित एक वर्ग बचा हुआ है। जिसका सत्ता के प्रतिष्ठानों पर भले ही प्रभाव ना हो, लेकिन तंत्र पर उसका प्रभाव अब भी है। मार्च 2022 में जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म आई थी। ‘द कश्मीर फाइल्स’ नामक इस फिल्म में एक संवाद है, सत्ता भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम अपना है। इस संवाद में जिस सिस्टम की ओर इशारा है, दरअसल तंत्र पर उसका ही प्रभाव है। कहना न होगा एक यह प्रभावी तबका वैसी ही उग्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, जिसके बारूदी रूख के अंत का ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिज्ञासु कार्यकर्ताओं ने इसे ‘अर्बन नक्सल’ कहा था। अर्बन यानी शहरी नक्सल।

भारत में नोएडा से औद्योगिक अशांति, दिल्ली-एनसीआर के कई राज्यों में फैली

डॉ. ज्ञान नोएडा के फेज-2 में प्रदर्शन हिंसक हो गया, और एक पुलिस वैन और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जहां कई औद्योगिक इकाइयों के कामगार दोपहर के आसपास वेतन बढ़ाने और दूसरे फायदों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद बिरोध प्रदर्शन नोएडा के दूसरे हिस्सों में फैल गये। प्रदर्शन की वजह से सुबह से ही ट्रैफिक पर असर पड़ा है। जैसे-जैसे भारत सरकार धीरे-धीरे नयी श्रम संहिताओं के नियमों को लागू कर रही है, भारतीय कामगारों में तनाव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से इसे पूरी तरह लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की थी, और अब 13 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में औद्योगिक अशांति शुरू हो गई, जो शीघ्र ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में फैल गई, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद और मानेसर (गुरुग्राम), राजस्थान के मिवाडी, दिल्ली और कई दूसरी जगहें शामिल हैं। औद्योगिक इलाकों में न सिर्फ

का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, है, भारतीय राजनीति में यह एक नया आयाम है, जहां केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के विकास की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों के बावजूद विकास की गति तेज रह सकती है, यदि नीतिगत समर्थन और प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो।बिहार के संदर्भ में यह पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, नेता के रूप में स्थापित करती है, जो केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन की वास्तविकताओं से ली जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व से बिहार की जनता को एक ऐसे प्रशासन की उम्मीद है जो नीतिगत स्पष्टता के साथ-साथ क्रियान्वयन की क्षमता भी रखता हो। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि बिहार में नेतृत्व का मूल्यांकन केवल व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों, प्राथमिकताओं में परिणामों के आधार पर होता है। पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सामने आई है कि शासन की सफलता का निर्धारण केवल मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि उस व्यापक नीति-ढांचे से होता है जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता

है, तो नया आयाम है, जहां केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के विकास की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के उदाहरण इस बात को पुष्ट करते हैं कि अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों के बावजूद विकास की गति तेज रह सकती है, यदि नीतिगत समर्थन और प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो।बिहार के संदर्भ में यह पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह राज्य लंबे समय तक अवसंरचनात्मक पिछड़ेपन, बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक विषमताओं से जूझता रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे इन जटिल समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करें। केवल राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उसे विकासात्मक स्थिरता में परिवर्तित करना होगा। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निरंतर सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर मिल सकें। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बिहार के हालिया इतिहास में यदि किसी नेता ने प्रशासनिक सुधार और सुशासन

माओवाद पर कैसे लगे

याद कीजिए, छह अप्रैल 2010 की घटना, जब बस्तर में सीआरपीएफ के हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण जैसे प्रसिद्ध बारूदी सुरंगों के जरिए उड़ाकर मार डाला था। इस लोमहर्षक कार्रवाई भारतीय राष्ट्र राज्य पर अर्बन नक्सल समुदाय ने बड़ी जीत के रूप में देखा था। राजधानी दिल्ली में लाल गढ़ के रूप में विख्यात जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने इस कार्रवाई पर खुलेआम खुशियां जताई थीं। तमाम विश्वविद्यालयों के वामपंथी प्रोफेसरों और छात्रों के एक समूह ने इस लोमहर्षक हत्या कांड को भारतीय राज व्यवस्था पर नक्सली अब भी है। मार्च 2022 में जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म आई थी। ‘द कश्मीर फाइल्स’ नामक इस फिल्म में एक संवाद है, सत्ता भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम अपना है। इस संवाद में जिस सिस्टम की ओर इशारा है, दरअसल तंत्र पर उसका ही प्रभाव है। कहना न होगा एक यह प्रभावी तबका वैसी ही उग्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, जिसके बारूदी रूख के अंत का ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिज्ञासु कार्यकर्ताओं ने इसे ‘अर्बन नक्सल’ कहा था। अर्बन यानी शहरी नक्सल।

राज्य के श्रम विभाग को स्थानीय अधिाकारियों और औद्योगिक इकाइयों से बातचीत करने के लिए कहा गया है।हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हर मजदूर को सम्मानजनक वेतन, काम करने का सुरक्षित माहौल और मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से श्रम कानूनों का पालन करने और मजदूरों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने नोएडा ाकारियों को मजदूरों को भड़काने की कथित तौर पर हिंसा भड़काई थी, और चेतावनी दी कि उनके खिलाफ सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने सचेत किया है कि लोगों को शलगभग खत्म हो चुके नक्सलवाद को फिर से जिंदा करने की साजिशश् से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, श्रमजदूरों के नाम पर उद्वरग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए।



प्रशासनिक मानक आज भी बिहार के लिए एक संदर्भ बिंदु बने हुए हैं। सम्राट चौधरी के लिए यह एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है कि वे इन स्थापित मानकों को न केवल बनाए रखें, बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाएं। उन्हें यह समझना होगा कि बिहार की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि परिणाम चाहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा के अवसर, अस्पतालों की स्थिति और चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार ऐसे क्षेत्र हैं जहां ठोस कार्य की आवश्यकता है। इसके साथ ही श्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो और गहरेबंधनों में बदलाव ने उनकी छवि को कुछ हद तक प्रभावित भी किया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित

माओवाद पर कैसे लगे लगात

किया। दो कृषि कानूनों के बदलाव के विरोध में लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को भी इस वैचारिकी का बुद्धिजीवी तो खुद ही मानते हैं कि वे इस विचारधारा से हैं। तंत्र में इस विचारधारा के प्रभावी होने की शुरुआत 1969 में कांग्रेस के विभाजन से होती है। तब अपनी केंद्रीय सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को वामपंथी दलों के सहयोग की जरूरत थी। उन्होंने सहयोग किया भी, बदले में शैक्षिक संस्थानों पर उनका प्रभाव बढ़ा। इसकी वजह यह रही कि इंदिरा सरकार ने शोध और शैक्षिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को इन्हीं के हवाले कर दिया। इस विचारधारा ने अपने ही लोगों को इन संस्थानों में खूब भरा। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो यह वैचारिकी पहले सक्रते में रही। बाद में इसने रणनीति और पैतरा बदला। शुरु में तो इस विचारधारा ने कभी पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में वैचारिकी आधारित आंदोलन छेड़ा तो कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों से छेड़खानी के बहाने राष्ट्रवादी विचारधारा को निशाने पर लेकर आंदोलन चलाया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित बेमुला के बहाने राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था के दौरान कथित तौर पर दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर वैचारिक आंदोलन खड़ा

से सामान्य जन पहचान नहीं पाता। शहरी नक्सलवादियों की एक खासियत यह है कि वे खासा पढ़ते लिखते हैं। इसलिए बहसों में उनकी भागीदारी प्रभावी रहती है। लेकिन भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का माखौल उड़ाना उन्हें सबसे प्रिय है। वेसे भारतीय शैक्षिक संस्थानों में एक सोच गहरे तक पैठी हुई है कि युवावस्था में जो वामपंथी को एकत्रित होने की वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी नक्सलियों का कितना बड़ा नेटवर्क है और कितनी गहराई तक उनकी पहुंच है। मोदी सरकार के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा को उम्मीद थी कि सत्ता केंद्रों और संस्थानों से इस विचारधारा की विदाई हो जाएगी। लेकिन अब भी यह विचारधारा प्रभावी तौर पर उपस्थित है। इस विचारधारा के कतिपय क्रांतिकारियों ने तो अब चोला तक बदल लिया है और मौजूदा सत्ता तंत्र में भागीदार भी बन चुके हैं। पत्रकारिता में अब भी इस विचारधारा के लोगों की संख्या है। इसकी वजह से अब भी नरैटिव का मायाजाल रचने में यह विचारधारा प्रभावी हो जाती है। नागरिक समाज में इस विचारधारा के लोग तभी पहचान में आते हैं, जब वे बहसों में हिस्सा लेते हैं या आंदोलनों में खुली भागीदारी करते हैं। अन्धथा समाज के सभी वर्गों की तरह इनको भी आसानी से आसानी से खाली पेट नहीं भर सकते। आंसू गैस के गोले भूख मिटा नहीं सकते। वर्कर्स की जायज मांगों को नजरअंदाज करना बंद करें और दमन का सहारा लेने के बजाय हल निकालें।श्ध्यान देने वाली बात यह है कि बेहतर वेतन के लिए आन्दोलन कर रहे मदरसन के सैकड़ों कामगार फैंक्टरी के अंदर घुस गए और वरिष्ठ अधिकारियों को वहां से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। नोएडा के फेज-2 में प्रदर्शन हिंसक हो गया, और एक पुलिस वैन और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जहां कई औद्योगिक इकाइयों के कामगार दोपहर के आसपास वेतन बढ़ाने और दूसरे फायदों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद बिरोध प्रदर्शन नोएडा के और कहा कि नोएडा में मदरसन कंपनी के बाहर के विजुअल स्परेशन करने वालेश् थे। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, श्जब महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और वेतन के नाम पर कामगारों का शोषण हो रहा है, तो युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।



आगजनी का तरीका, खासकर जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई, क्या पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर अशांति भड़काने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों से मेल खाता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा में कामगारों के हिंसक विरोध। प्रदर्शन के लिए भाजपा सरकार की श्फ़करतफा नीतिश् को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि सरकार पूर्वूजीपतियों का पक्ष लेती है जबकि वेतनभोगी कर्मचारियों और मजदूरों को रहीं है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान

शाही विरासत का नया रूप, लखनऊ में सजी मेहरुनिसा की प्रदर्शनी



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। शहर में शाही अंदाज और आधुनिक सोच का अनूठा मेल देखने को मिलेगा। "मेहरुनिसा बाय शमिता" अपनी खास ज्वेलरी प्रदर्शनी लेकर आ रही हैं। 17 और 18 अप्रैल को जोपलिंग रोड स्थित फॉर्च्यून होटल में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में विरासत को आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। इसमें पुराने राजसी डिजाइनों को नए रूप में पेश किया गया है। मेहरुनिसा की फाउंडर और डिजाइनर शमिता शर्मा ने 30 साल पहले इस ब्रांड की स्थापना की थी। उनका मुख्य फोकस

ट्रेडिशनल पोल्की और जड़ाऊ ज्वेलरी को दोबारा नये अंदाज में लोगों के बीच प्रचलित करना है। शमिता अपनी ब्राइडल और स्टेटमेंट पीस के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। मेहरुनिसा के एग्जिबिशन पिछले 30 वर्षों से भारत के विभिन्न शहरों और विदेशों में आयोजित किये जाते रहे हैं। यह ब्रांड पोल्की और डायमंड फाइन ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है, जो शाही शिल्पकला और टाइमलेस क्लासिक डिजाइनों को आधुनिक रूप देता है। शमिता शर्मा अपनी क्रिएटिविटी और हेरिटेज को दोबारा प्रचलित करने के लिए जानी जाती हैं। शमिता शर्मा ने

बताया कि मेहरुनिसा में हर गहना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि एक विरासत है। मेरी कोशिश है कि हमारी पुरानी कला जिंदा रहे और आज की महिलाओं के लिए भी उतनी ही खास बने। इस प्रदर्शनी में दुल्हन के लिए खास पोल्की ज्वेलरी, एंटीक गोल्ड और जड़ाऊ कलेक्शन के साथ-साथ डायमंड और स्टेटमेंट पीसेज भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में पहने जा सकने वाले हल्के लेकिन खूबसूरत गहनों की भी अच्छी रेंज मौजूद होगी। प्रदर्शनी में शादी-ब्याह के गहनों से लेकर त्योहारों और मॉडर्न लुक के लिए डिजाइन किए गए पीसेज का भी खास कलेक्शन है। खास बात यह है कि यहां आने वाले मेहमानों को डिजाइनर शमिता शर्मा से सीधे बातचीत और स्टूडिओ सलाह लेने का मौका भी मिलेगा। मेहरुनिसा की खासियत पारंपरिक कारीगरी को आगे बढ़ाना है। जड़ाऊ, पोल्की और हाथ से की गई बारीक नक्काशी को फिर से जीवित करने के साथ-साथ नए कारीगरों को भी इन तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर गहना हॉलमार्कड गोल्ड और प्रमाणित स्टोन्स से तैयार किया गया है।

'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिये 30 मई तक करे आवेदन-सुष्मिता सिंह'

'रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव' हरदोई जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सुष्मिता सिंह ने बताया है, कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 10 इकाईयाँ पूँजी निवेश 50.00 लाख एवं 200 रोजगार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 शासन द्वारा अधिक से अधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शिक्षित बेरोजगारों पालिटैक्निकल आई०टी०आई० पास तकनीकी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त एवं परम्परागत कारीगरों तथा व्यवसायिक शिक्षा (10-12) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय

लेकर उत्तीर्ण छात्रछात्राओं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो ऐसे इच्छुक नवयुवक नवयुवतियों से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल उचहतलीकप.नचेकब.हवअ.पद पर 30 मई, 2026 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत रू०-10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमत्य हैं। जिनमें सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कार्ट का 10 प्रतिशत अंशदान तथा टर्मलोन (पूँजीगत ऋण) पर 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा शेष ब्याज उपादान टर्मलोन पर शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने के दशा में उपलब्ध कराया जायेगा,

इसके अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों एवं सभी वर्ग की महिलाओं को प्रोजेक्ट कार्ट का 5 प्रतिशत अंशदान तथा (पूँजीगत ऋण) पर समस्त ब्याज उपादान शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंक के द्वारा लूके के माध्यम से किया जायेगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल पर अपना फोटो, शैक्षित योग्यता, आर कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रमाण द्वारा सत्यापित कार्यस्थल की प्रमाणित प्रमाण-पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेवसाइड पर अपलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, हरदोई किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 'नारी शक्ति वंदन' का सजीव प्रसारण, छात्राओं ने रंगोली व पदयात्रा से जताया समर्थन



ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में शुक्रवार को 'नारी शक्ति वंदन' से जुड़े संसदीय सत्र का सजीव प्रसारण सामूहिक रूप से देखा गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक

भाग लेते हुए महिलाओं के सशक्त नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी के समर्थन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान सभागार में गंभीरता, जागरूकता और उत्साह का माहौल देखने को मिला। उपस्थित सभी लोगों ने इस ऐतिहासिक पहल को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और समाज में महिलाओं की

समान भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कुलसचिव केशलाल, परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह, प्रो. प्रमोद कुमार यादव, कार्यक्रम संयोजक डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव सहित प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. प्रदीप कुमार, प्रो. गिरिधर मिश्र, प्रो. प्रमोद कुमार, डॉ. रसिकेश, डॉ. मनोज कुमार पांडेय, डॉ. रामांशु प्रभाकर सिंह, डॉ. नितेश जायसवाल एवं अन्य शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। इसके पश्चात रज्जू भैया संस्थान में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने 'नारी शक्ति वंदन' के समर्थन में आकर्षक रंगोलियाँ बनाईं। प्रतियोगिता में विभिन्न समूहों के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल में प्रो. प्रमोद यादव और प्रो. मिथिलेश सिंह शामिल रहे। बज्रंग दल, गुरुवार की देर शाम विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास की छात्राओं ने एडिशनल चीफ वार्डन डॉ. अन्नू त्यागी के नेतृत्व में 'नारी शक्ति वंदन' के समर्थन में विशाल पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में सभी छात्रावासों की छात्राओं ने बड़-चढ़कर भाग लिया और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

अब तक 1.05 लाख बच्चे के हुए प्रवेश, निजी स्कूलों में दाखिले का एक सप्ताह और मिलेगा मौका

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नए सत्र में 1.95 लाख के सापेक्ष अब तक 1.05 लाख प्रवेश हुए हैं। बचे हुए लगभग 90 हजार बच्चों के प्रवेश के लिए एक सप्ताह का समय बसिक शिक्षा विभाग ने और बढ़ा दिया है। इसके तहत अभियान चलाकर जिलों में प्रवेश कराया जाएगा। इस बार तीन चरणों में ही आवेदन लिए गए और अप्रैल से पहले प्रक्रिया पूरी कर ली गई। समग्र शिक्षा के उप निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि वे बचे हुए बच्चों को प्रवेश दिलाएं। सभी जिलों से हर दिन गूगल शीट से प्रवेश पाने वाले बच्चों की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। जिनका प्रवेश नहीं हो रहा है, उसका कारण भी बताना होगा। जो स्कूल प्रवेश नहीं ले रहे हैं उन्हें नोटिस जारी की जाए। होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41424 पदों पर भर्ती के लिए अगामी 25 से 27 अप्रैल तक होने वाली लिखित परीक्षा की उत्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड फूलप्रूफ तैयारी कर रहा है। बोर्ड 23 अप्रैल को परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए रिहर्सल करेगा। इस दौरान कोषागारों से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की ड्रिल भी होगी। बोर्ड के अध्यक्ष एसबी शिरडकर ने बताया कि परीक्षा के आयोजन से पहले 18 अप्रैल को यूपी 112 मुख्यालय में सभी नोडल अधिकारियों, पर्यवेक्षकों आदि की बैठक होगी।

अमर रसोई गैस बीकापुर पर इतनी भीड़ उपभोक्ताओं की क्यों लग रही बना एक प्रश्न

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर) अयोध्या।बीकापुर में संचालित की जा रही अमर रसोई गैस अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रही है। भारत गैस एजेंसी के उपभोक्ता घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पूछताछ काउंटर पर कोई कर्मचारी ना तो बैठते हैं, और ना ही कुछ बताने के लिए तैयार है। और ना ही उनके पास कोई पूछताछ काउंटर है। सही चीज क्या है, यह उपभोक्ताओं से छुपाई जा रही है। यूपी के सीएम का आदेश है कि जितने भी गैस कनेक्शन धारी है उनको गैस लेने अब केंद्र पर नहीं आना पड़ेगा गैस एजेंसी के प्रबंधक उनको घरे पर गैस पहुंचाएंगे। उपभोक्ता यही सोचकर टकटकी लगाए देखा रहता है कि, हे भगवान कब तक गाड़ी आयेगी लेकिन देखते-देखते शाम हो जाती है। और कोई गैस नहीं आती। यदि ऐसा होता तो लोग जो वीडियो में

दिख रहे हैं इतनी भीड़ क्यों लगाते। यहां पर तो सरेशाम यूपी के मुख्यमंत्री के आदेशों की ध्वजियां उड़ाई जा रही है। अमर गैस रसोई के प्रबंधक इन दिनों अनुपस्थित चल रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में चार्ज किसको दिया गया है। इसको बताने वाला यहां पर कोई नहीं है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहां तक मोबाइल पर अपने आप मैसेज आ जाता है कि आपकी डिलीवरी हो गई। जबकि उस उपभोक्ता को अभी तक गैस मिला ही नहीं। नोटिस बोर्ड पर सूचना के माध्यम से गैस उपभोक्ताओं को सूचना दी गई है की इस सप्ताह में फला फला दिन गांव-गांव जाकर लोगों के घर पर गैस पहुंचाई जाएगी तो वीडियो में आप देख रहे हो अगर सब कुछ आल इज वेल है। तो भारत गैस एजेंसी बीकापुर पर लोग भीड़ क्यों लगा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो जिस काउंटर पर उपभोक्ता लाइन में खड़े होकर अपनी ओटीपी

आने का इंतजार कर रहे हैं ना तो उस जगह पर पानी पीने की व्यवस्था है। और ना ही उनके सर पर छत है। इतनी तेज धूप में लोग घंटों लाइनों में खड़े होने को विवश हैं। एक बात और इनके यहां एक खिड़की पीछे दरवाजे से है जहां पर जुगाड़ों और पकड़दार किस्म के लोग जाते हैं। और इशारों इशारों में बात करके अपना काम करके चले जाते हैं। जो लाइन में लगा है लग रहे उनको उनसे कोई मतलब नहीं। अमर रसोई गैस बोर्ड पर दिए गए नंबर पर जब गैस कनेक्शन के उपभोक्ता फोन करते हैं। तो घंटी तो बजती है लेकिन फोन रिसीव नहीं होता। और सूत्रों की माने तो बोर्ड पर दिए गए नंबर पर उन्हीं लोगों का फोन रिसीव किया जाता है जो उनकी टच में है। और उनको आना भी नहीं पड़ता है। अमर रसोई गैस एजेंसी पर वीडियो के माध्यम से दिख रही भीड़ के अनुसार अनुमान दिए लगाया जा रहा है कि यहां पर उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है।

नारी शक्ति वंदन एवं विधानसभा सम्मेलन संपन्न



(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ) अयोध्या।आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारागंज परिसर स्थित ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन एवं विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वर्तमान सांसद लल्लू सिंह एवं विशिष्ट अतिथि मिलिन्कीपुर विधायक चंद्रभान पासवान रहे।शुक्रवार को ऑडिटोरियम हाल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिभा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुआ। कार्यक्रम में मौजूद नारी शक्तियों का सम्मान उन्हें अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि महिलाओंको 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाए जाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के जमाने से शुरू हुआ था और पंचायत स्तर पर लागू भी हो गया था। किंतु उसे विधानसभा और लोकसभा स्तर पर लागू किए जाने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत थे, जिनकी अपार मेहनत और कोशिशों

के बाद महिला आरक्षण बिल आज अथवा कल में सदन में पास हो जाएगा। उन्होंने कहा किभगवान से लेकर आम जन के उत्थान में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मां के समर्पण के एवं त्याग के चलते ही तमाम धर्म युद्ध जीते गए हैं। देश में नारी का स्थान सदैव हो रहा है।लोकतंत्र लागू होने एवं भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार प्रयास हुए और आज वह महिला आरक्षण बिल लागू होने जा रहा है। निर्माण व संयोजन का काम केवल महिलाओं का है।उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी मातृ शक्तियों को आगाह करते हुए कहा कि अधिकार के साथ-साथ त्याग एवं समर्पण का भाव भी आप सब में बना रहे। उन्होंने सभागार में मौजूद महिलाओं को बधाई भी दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक चंद्रभान पासवान ने कहा कि नारी शक्ति को सर्वशक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने नारी को सृजन की आधार शिला बताया। उन्होंने कहा कि आज की नारी आत्मनिर्भर बन रही है। असली वंदन तभी होगा जब समाज में बदलाव आए। महिलाओं

बजरंग दल का बड़ा प्रदर्शन जिहादी मानसिकता, अवैध कब्जों के खिलाफ राष्ट्रपति को झापण सौंपा

ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। यूपी के जौनपुर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) बजरंग दल के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम 5 बजे एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन देश में बढ़ती शक्ति जिहादी मानसिकताश, अवैध कब्जों और सुनिश्चित पडचंत्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर पॉलिटेक्निक चौराहा, कृषि भवन के निकट से शुरू हुआ। यह बाजिदपुर तिराहा और जेसीज चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट में एक सभा के रूप में समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक झापण सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को सौंपा। बजरंग दल के जिला मिलन केंद्र प्रमुख आशुतोष सिंह ने इस अवसर पर कहा कि देश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने वाली श्जिहादी मानसिकताश अब राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और सद्भाव के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। उन्होंने इस मानसिकता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला संयोजक समर बहादुर सिंह ने कहा कि हाल ही में सामने आए कुछ प्रकरणों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नासिक में टीसीएस (जे) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के आसपास उजागर हुए मामले यह दर्शाते हैं कि श्लव जिहादश का जाल अब सुशिक्षित समाज और व्यावसायिक क्षेत्रों तक फैल चुका है। अमरावती में मोहम्मद अयाज नामक व्यक्ति द्वारा



180 नाबालिग हिंदू लड़कियों का कथित तौर पर शोषण कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला भी सामने आया है। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि देशभर में जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों का शारीरिक शोषण, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कृत्य समाज में अशांति और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। संगठन ने देश के विभिन्न नगरों में वन भूमि, सार्वजनिक भूमि, रेल विभाग और सेना की सुरक्षित भूमि पर सुनिश्चित तरीके से किए जा रहे सिंह ने कहा कि हाल ही में सामने आए कुछ प्रकरणों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नासिक में टीसीएस (जे) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के आसपास उजागर हुए मामले यह दर्शाते हैं कि श्लव जिहादश का जाल अब सुशिक्षित समाज और व्यावसायिक क्षेत्रों तक फैल चुका है। अमरावती में मोहम्मद अयाज नामक व्यक्ति द्वारा

बजरंग दल ने मांग की कि ऐसी राष्ट्र विरोधी और आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध त्वरित एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संगठन ने श्लव जिहादश और जबरन धर्मांतरण जैसे कृत्यों को रोकने हेतु एक कठोर धर्मांतरण की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कृत्य समाज में अशांति और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। संगठन ने देश के विभिन्न नगरों में वन भूमि, सार्वजनिक भूमि, रेल विभाग और सेना की सुरक्षित भूमि पर सुनिश्चित तरीके से किए जा रहे सिंह ने कहा कि हाल ही में सामने आए कुछ प्रकरणों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नासिक में टीसीएस (जे) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के आसपास उजागर हुए मामले यह दर्शाते हैं कि श्लव जिहादश का जाल अब सुशिक्षित समाज और व्यावसायिक क्षेत्रों तक फैल चुका है। अमरावती में मोहम्मद अयाज नामक व्यक्ति द्वारा

सांक्षिप्त खबरें चालक को आई झपकी, ट्रेलर घर में घुसा, दो लोग घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। फुलवरिया बार्डपास पर बुधवार शाम करीब पांच बजे अनियंत्रित ट्रेलर सफाई कर्मचारी सुरेश कुमार के घर में जा घुसा। चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि मकान का बरामदा ढह गया और घर में मौजूद सुरेश कुमार (45) गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीण और पुलिसकर्मी जमा हो गए। उन्होंने ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक अलीम (35) को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस्पेक्टर बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेलर बनी सड़क की ओर जा रहा था। हादसे के वक्त घर में मौजूद सुरेश लहलुहा हकी गए। घटना के दौरान घर में मौजूद अन्य 16 सदस्य बच गए। इस्पेक्टर ने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुरेश के मकान में उनके तीन सगे भाई पप्पू और राजू के परिवार भी रहते हैं। घटना के समय परिवार के कई सदस्य घर में मौजूद थे। सोना ने बताया कि अचानक तेज आवाज के साथ घर की दीवारें हिल गईं। सभी लोग जान बचाकर पीछे के दरवाजे से बाहर भागे। हादसे के बाद लगभग दो घंटे तक बार्डपास पर आवागमन ठप रहा।

पर्यटन रू के सौन्दर्यीकरण व विकास के लिए 10.19 करोड़ रुपये स्वीकृत

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों में पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण, नवनिर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमानित लागत का आकलन करते हुए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त जारी कर दी गई है, जिससे विकास कार्यों को शीघ्र गति मिल सकेगी।यह जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या मंडल के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधानसभाओं के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर प्रथम किस्त की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि आलापुर क्षेत्र के संत बाबा गोविन्द साहब की तपोभूमि अहिरौली के पर्यटन विकास के लिए 60 लाख रुपये, कटहरी विधानसभा के भीठी स्थित काली मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 62 लाख रुपये तथा अकबरपुर चौतीपारा में ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।पर्यटन मंत्री ने बताया कि अकबरपुर के लोरपुर में स्थित महाराजा सुहेलदेव राजभर वंशीय अष्टछम्भा स्तूप के पर्यटन विकास के लिए 78 लाख रुपये तथा अकबरपुर के ही अम्बेडकरनगर स्थित श्रवण क्षेत्र के विकास के लिए 262 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त टांडा विकासखंड बसखारी में फलाहारी महाराज एवं अंगीरा मुनि के आश्रम के पर्यटन विकास हेतु 75 लाख रुपये तथा जलालपुर स्थित बाबा झारखण्ड स्थल के विकास के लिए 75 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।इसी प्रकार अमेठी जनपद के विधानसभा क्षेत्र जानदीशपुर स्थित महावीर मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 75 लाख रुपये, तिलोई क्षेत्र के कुटीसेवापुर स्थल के विकास हेतु 95 लाख रुपये तथा गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के मुसाफिरखाना में बाबा महावीरदास मंदिर के विकास के लिए 58 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पूर्व सैनिक कल्याण निगम की सुरक्षा सेवाओं पर बढ़ा भरोसा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा सेवाओं से संतुष्ट होकर राज्य के विभिन्न विभागों ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अपने अनुबंधों का नवीनीकरण कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम की सेवाएं संतोषजनक पाए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की कार्रवाइयें प्रक्रिया में हैं।निगम के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल शरद बिक्रम सिंह (रिटायर्ड) ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार तथा प्रदेश प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निगम पर जताया गया विश्वास पूर्व सैनिकों के समर्पण और अनुशासन का प्रमाण है।अनुबंध नवीनीकरण कराने वाले प्रमुख विभागों में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसरचरणा विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।नवीनीकृत अनुबंध 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिए गए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि भविष्य में भी सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक विभाग निगम की सेवाओं का लाभ उठा सकें।

कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 187 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लखनऊ मंडल का सामूहिक विवाह कार्यक्रम अवध शिल्प ग्राम वृन्दावन, सेक्टर-09, शहीद पथ, लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ मंडल के जनपद लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली एवं हरदोई के कुल 187 जोड़ों, जिनमें 176 हिन्दू एवं 11 मुस्लिम जोड़े शामिल थे, का विधिवत सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर द्वारा की गई। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी आगंतुकों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मंत्री अनिल राजभर ने अपने संबोधन में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कन्या विवाह सहायता योजना श्रमिक परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए पुष्प वर्षा भी की।कार्यक्रम को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करते हुए अंबेडकर नगर के कलाकारों द्वारा विवाह गीत प्रस्तुत किए गए, जिसने आयोजन को पारंपरिक और भावनात्मक वातावरण से सराबोर कर दिया। उपस्थित लोगों ने इन प्रस्तुतियों की सराहना की।कार्यक्रम में सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह की प्रतिनिधि भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने लखनऊ के नवविवाहित जोड़ों को वर-वधु के लिए वस्त्र एवं 501 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए। इस अवसर पर बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

